सरकारी निकायों में ई-ऑफिस क्रियान्वन

[स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स]

भारत सरकार ने **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances-DARPG) की 100-दिवसीय कार्य-सूची** के हिस्से के रूप में **ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म** का सभी संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में क्रियान्वन किये जाने की घोषणा की।

- ई-ऑफिस पहल का उद्देश्य **विभिन्न सरकारी निकायों में फाइल हैंडलिंग और रसीदों को डिजिटल बनाना** है। यह पहल वर्ष 2019 से 2024 की अवधि में केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में आई उल्लेखनीय गति को दृष्टिगत रखते हुए की गई है, जहाँ **94 प्रतिशत फाइलों को ई-फाइल के रूप में और 95 प्रतिशत रसीदों को ई-रसीद के रूप में संभाला गया**।
- इस सफलता के आधार पर, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ई-ऑफिस पहल के क्रियान्वन के लिये 133 संस्थाओं की पहचान की है। इसे अपनाने हेतु दिशा-निर्देश DARPG और **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा जारी किये गए थे।
  - डिजिटल परिवर्तन और प्रशासनिक दक्षता के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए सभी मंत्रालय/विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, डेटा सेंटर स्थापित करेंगे तथा ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निर्बाध, समयबद्ध क्रियान्वन के लिये NIC के साथ समन्वय करेंगे।

और पढ़ें: भारत में ई-गवर्नेंस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-office-implementation-in-government-bodies